दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३३१ वा | बुधवार २ जुलै २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

धनंजय मुंडे के सनसनीखेज आरोपों पर संदीप क्षीरसागर का पलटवार

कहा-मैं उनके जैसा १५० दिन भागा नहीं!

बीड, १ जुलाई (प्रतिनिधि): बीड के एक निजी कोचिंग क्लास में NEET की तैयारी कर रही १७ वर्षीय छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटना ने जिले में भारी हलचल मचा दी है। इस मामले में POCSO के तहत मामला दर्ज किए गए आरोपी विजय पवार को विधायक संदीप क्षीरसागर का नजदीकी बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी नाते उसे बीड शिवजयंती महोत्सव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।

घटना के दिन ही आरोपी विजय पवार विधायक संदीप क्षीरसागर के साथ मौजूद था, और अगले दो दिनों में पीड़िता के पिता को २० बार फोन किए गए - यह गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के नेता व पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने लगाए थे।

इन आरोपों पर अब विधायक संदीप क्षीरसागर ने पलटवार करते हुए कहा, धनंजय मुंडे की एसआईटी जांच की मांग का मैं समर्थन करता हूँ। जो घटना हुई वह गलत है। आरोपी शिक्षक को घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने खुद पुलिस प्रशासन से कहा है कि चाहे वह मेरा नजदीकी ही

क्यों न हो, कार्रवाई में कोई ढील नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, इस मामले में अपराध दर्ज करने में १० दिन नहीं लगे। जैसे ही पीड़िता ने शिकायत दी, एफआईआर दर्ज हुई। मैं धनंजय मुंडे की तरह १५० दिन के लिए कहीं भागा नहीं था। उन्हें मंत्रीपद चला गया है, इसीलिए शायद वे आहत हैं। लेकिन जब मस्साज प्रकरण हुआ था, तब उन्हें उतनी ही आक्रामक भूमिका लेनी चाहिए थी जितनी आज ले रहे हैं।

विधायक क्षीरसागर ने कहा कि बीड के संपर्क मंत्री अजित पवार हैं और उन्हें प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस तत्परता से काम कर रही है और CCTV फुटेज भी कब्जे में लिए गए हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह खुद पीड़िता से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा करना उचित नहीं लगा, इसलिए रुके हुए हैं। मैं रोज़ आम जनता के बीच रहता हूँ, चाय की टपरी पर जाता हूँ, लोग मिलते हैं। जिनका नाम आ रहा है, वे मेरे परिचित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई दोषी है तो कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा उन्होंने जोर देकर कहा।

इस तरह बीड की राजनीति में यह मामला एक बड़ा विवाद बन गया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं।

बीड यौन उत्पीड़न मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी' गठित होगी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, १ जुलाई (जमीर काज़ी)

बीड में १७ वर्षीय नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के सनसनीखेज मामले की गहन जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की जाएगी, जो इस प्रकरण की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच करेगी। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति या नेता दोषियों को बचाने का प्रयास करेगा, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद बीड जिला लगातार आपराधिक घटनाओं के कारण चर्चा में है। इसी पृष्ठभूमि में बजट सत्र के पहले ही दिन धनंजय मुंडे को अपने मंत्रीपद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब बीड के एक निजी कोचिंग क्लास में एक १७ वर्षीय छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिससे मुंडे और विधायक संदीप क्षीरसागर आमने-सामने हैं।

इस मुद्दे को आज विधायक चेतन तुपे ने विधानसभा में उठाया और आरोप लगाया कि आरोपी के राजनीतिक संबंधों के चलते उसे संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है।

शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करने की मांग पर विपक्ष का विधानमंडल की सीढ़ियों पर जोरदार आंदोलन

विशेष संवाददाता । मुंबई, २ जुलाई

पावसाळी अधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। मंगलवार को महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शक्तिपीठ महामार्ग को रद्द करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर जोरदार नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया।

प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने एक ही जिद्द, शक्तिपीठ रद्द, शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो जैसे तीखे नारे लगाए। उनका आरोप था कि

यह महामार्ग किसानों के लिए अन्यायकारी है और उन्हें बर्बादी की कगार पर ला रहा है।

इस अवसर पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरित क्रांति के जनक वसंतराव नाईक की जयंती भी मनाई गई। मुंबई स्थित विधान भवन परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और राज्य को अन्न में आत्मनिर्भर बनाने वाले इस नेता की स्मृति को सम्मानपूर्वक याद किया गया।

आंदोलन में विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वड्डेटीवार, सतेज पाटील, जितेंद्र आव्हाड और ज्योति गायकवाड़ समेत कई अन्य नेता उपस्थित रहे। विपक्ष ने साफ किया कि जब तक यह महामार्ग रद्द नहीं होता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

राजेश कुमार बने महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव; सुजाता सौनिक से पदभार ग्रहण

रिपोर्ट: जमीर काज़ी । मुंबई

महाराष्ट्र सरकार के नए मुख्य सचिव पद पर सोमवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव सुजाता सौनिक से राज्य के ४९वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया।

इस अवसर पर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं को तेज गति से लागू करने की दिशा में वे प्रयासरत रहेंगे ताकि आम नागरिकों को मंत्रालय तक बार-बार ना आना पड़े। हालांकि वे दो महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में यदि उन्हें कार्यकाल विस्तार नहीं मिला तो उनका कार्यकाल केवल दो महीने का रहेगा।

राजेश कुमार का संक्षिप्त परिचय

राजेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (ख-ड) के १९८८ बैच के अधिकारी हैं। उनका जन्म ३ अगस्त १९६५ को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में हुआ। उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है और २५ अगस्त १९८८ को प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए।

उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत २४ जुलाई १९८९ को सोलापुर में अधिसंख्य सहायक जिलाधिकारी के पद से की। इसके बाद वे सातारा के सहायक जिलाधिकारी, बीड जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमरावती में आदिवासी विकास के अपर आयुक्त, धाराशिव और जळगांव के जिलाधिकारी, सोलापुर महापालिका आयुक्त, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री के निजी सचिव, नाशिक में आदिवासी विकास आयुक्त, नवी मुंबई में एकीकृत बाल विकास आयुक्त, मंत्रालय में जलापूर्ति विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, सहकार एवं वस्त्रोद्योग विभाग तथा राजस्व एवं वन विभाग के अपर मुख्य सचिव जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।

राजेश कुमार के नेतृत्व में शासन प्रशासन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जलसंधारण विभाग में ८,७६७ पदों को मिली मंजूरी, जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया : मंत्री संजय राठोड़

मुंबई, १ जुलाई (जमीर काज़ी)

महाराष्ट्र सरकार ने जलसंधारण विभाग के लिए ८,७६७ नए पदों को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी जलसंधारण मंत्री संजय राठोड़ ने विधान परिषद में दी। उन्होंने बताया कि विभाग ने एक नया पद संरचना प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे 'हाय पॉवर कमिटी' ने मंजूरी दे दी है।

अब जल्द ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (चझडउ) के माध्यम से इन पदों की भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जाएगी।

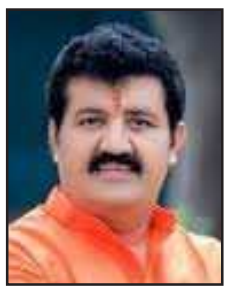

हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की है कि जब विभाग में १६,००० पद रिक्त हैं, तब भी सभी पदों को मंजूरी नहीं मिल रही, जिससे मंत्री विवश नजर आ रहे हैं।

यह मुद्दा विधान परिषद में डॉ. प्रज्ञा सातव, अभिजित वंजारी, ड. अनिल परब और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे द्वारा उठाया गया था।

मंत्री राठोड़ ने जानकारी दी कि २०१७ में जलसंधारण विभाग की स्वतंत्र स्थापना की गई थी, तब १६,४९९ पदों का ढांचा मंजूर किया गया था। इनमें से ९,९६७ पद कृषि विभाग से और ६,५१२ पद जलसंपदा व ग्रामविकास विभाग से हस्तांतरित होने थे, लेकिन कृषि विभाग से केवल २,१८१ पदों की ही मंजूरी मिली है। मंत्री राठोड़ ने यह भी घोषित किया कि इन नए पदों के माध्यम से विभाग की संरचना को अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर में अपर आयुक्त का नया कार्यालय स्थापित किया जाएगा, साथ ही पालघर, वर्धा, सिंधुदुर्ग, लातूर, कोल्हापुर, रत्नागिरी और रायगड जिलों में जलसंधारण अधिकारियों के नए कार्यालय शुरू किए जाएंगे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

बीड में सहकार संकुल निर्माण के लिए 90 करोड़ की निधि स्वीकृत

विधायक विजयसिंह पंडित की मांग को मिली मंजूरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार का आभार

मुंबई, ०१ जुलाई (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं बीड जिले के संपर्क मंत्री अजित पवार द्वारा बीड जिले के विकास कार्यों को दी जा रही मंजूरी से जिले के गौरव में लगातार वृद्धि हो रही है। बीड शहर में सहकार विभाग की भूमि पर एक भव्य सहकार संकुल इमारत निर्माण की मांग विधायक विजयसिंह पंडित ने की थी। इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ४ जून को इस परियोजना के लिए १४ करोड़ ९८ लाख रुपये के खर्च को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी प्रदान की थी।

अब विधानमंडल के पावस सत्र की अनुपूरक मांगों में इस कार्य के लिए १० करोड़ रुपये की ठोस तरतुद (वित्तीय प्रावधान) की गई है। इस पर विधायक पंडित ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजित पवार का आभार व्यक्त किया है।

यह संकुल बीड शहर के जालना रोड क्षेत्र में स्थित नगर भूमापन क्रमांक १७९९ की सहकार विभाग की जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें सहकार विभाग के अधीनस्थ १० क्षेत्रीय कार्यालयों को एक ही छत के नीचे स्थान मिलेगा, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

विधायक विजयसिंह पंडित ने इस कार्य के लिए सरकार स्तर पर निरंतर प्रयास किए थे। उन्होंने बताया कि यह इमारत बीड शहर के मध्यवर्ती हिस्से में १५१५.९७ वर्ग मीटर क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के मार्गदर्शन में एक भव्य व आधुनिक भवन के रूप में खड़ी की जाएगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी सुगमता आएगी और आम नागरिकों को बेहतर सेवा मिलेगी।

विधायक पंडित ने कहा कि बीड जिले के संपर्क मंत्री बनने के बाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा जिले को भव्य सहकार संकुल की सौगात देना गौरव की बात है और इसके लिए वे उनके विशेष रूप से आभारी हैं।

कांग्रेस में माजी मंत्री राजेंद्र मुळूक की 'घरवापसी', निलंबन औपचारिक रूप से वापस

मुंबई, १ जुलाई । रिपोर्ट : जमीर काज़ी

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राजेंद्र मुळूक की मंगलवार को कांग्रेस पार्टी में औपचारिक रूप से 'घरवापसी' हो गई। विधानसभा चुनाव में बगावत करने के कारण उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था, लेकिन अब दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया।

२०१९ के विधानसभा चुनाव में रामटेक विधानसभा सीट महा विकास आघाड़ी के अंतर्गत शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को दी गई थी। इससे नाराज़ होकर मुळूक ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी के तहत सभी दल अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस नेतृत्व ने मुळूक को दोबारा पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया।

दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला की मौजूदगी में मुळूक का निलंबन औपचारिक रूप से वापस लिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने उनका पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बी.एम. संदीप और कुणाल चौधरी भी उपस्थित थे। राजनीतिक गलियारों में मुळूक की घरवापसी को आगामी चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है।

राज्य के राजस्व राज्यमंत्री पर वाळू चोरी का आरोप, तीन दिन में पेश होंगे पक्के सबूत-अनिल परब

मुंबई, १ जुलाई (जमीर काज़ी)

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) के वरिष्ठ विधायक अनिल परब ने मंगलवार को विधान परिषद में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के राजस्व राज्यमंत्री वाळू (रेत) चोर हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस आरोप से जुड़े पाँच ठोस प्रमाण मौजूद हैं, जो वे आगामी तीन दिनों में सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

हालांकि परब ने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि राज्य के राजस्व राज्यमंत्री योगेश कदम हैं, इसलिए संकेत स्पष्ट हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आश्वासन दिया कि अगर सबूत पेश किए जाते हैं, तो वे इसी सत्र में इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देंगे।

परब ने कहा, अगर कोई लोकसेवक अपराध करता है तो सरकार के पास कार्रवाई का अधिकार है। मंत्री और विधायक भी लोकसेवक की परिभाषा में आते हैं। राजस्व राज्यमंत्री ने पांच स्थानों पर वाळू पकड़ी, जिसे सरकार की नीति के अनुसार तहसील कार्यालय को सौंपा जाना था और गरीबों में बाँटने का निर्देश था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी है।

उन्होंने सीधे तौर पर सरकार से सवाल किया, जो कठोरता आप तहसीलदार और आरटीओ अधिकारियों पर दिखाते हैं, वही सख्ती क्या आप अपने राज्यमंत्री पर दिखाएंगे? या फिर वे अपवाद हैं?

अनिल परब ने यह भी कहा कि वे मंत्री के दौरे से संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और रिपोर्ट की प्रतियाँ सदन को देंगे और पूछा कि क्या ऐसे में मंत्री को निलंबित किया जाएगा?

इस पर विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने परब द्वारा इस्तेमाल किए गए महसूल राज्यमंत्री वाळूचोर आहेत (राजस्व राज्यमंत्री वाळू चोर हैं) शब्द को सदन के पटल से हटाने के निर्देश दिए।

योगेश कदम का पलटवार : सबूत दो, इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लूंगा

राजस्व राज्यमंत्री योगेश कदम ने प्रेस को संबोधित करते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, विपक्ष के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण हैं तो सामने लाएँ। अगर आरोप सिद्ध होते हैं, तो मैं तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। उन्होंने इसे व्यक्तिगत बदनामी का प्रयास करार देते हुए कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर कानूनी जवाब भी देंगे।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विधायक अनिल परब द्वारा वादा किए गए 'पाँच प्रमाण' अगले तीन दिनों में पेश होते हैं या नहीं, और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।

महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य, हिंदी पर भी गर्व; दबाव में आए बिना छात्रों के हित में लेंगे निर्णय : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, १ जुलाई (जमीर काज़ी)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र में एकमात्र अनिवार्यता मराठी भाषा की है। मराठी सीखनी ही होगी, इसमें कोई छूट नहीं, ऐसा कहते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि हमें हिंदी पर भी गर्व है और भारत की हर भाषा का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अंग्रेजी को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं को दबाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक समिति गठित की है और वह किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक दबाव में आए बिना विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेगी।

फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने मुंबई का चेहरा बदल दिया, लेकिन आप (ठाकरे) मराठी माणूस को शहर से बाहर निकालने का काम कर रहे थे। ठाकरे सरकार द्वारा गठित समिति ने पहली से बारहवीं तक मराठी के साथ हिंदी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य करने की सिफारिश की थी।

आप केवल मराठी के नाम पर राजनीति करते रहे, जबकि मराठी लोगों को घर देने का काम हमने किया, फडणवीस ने कहा। बीबीडी चॉल में हमने घर दिए, धारावी के गरीबों को भी हमने घर दिए। चुनाव आते ही आपको मराठी माणूस याद आता है।

राजनीति पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा, हम यह नहीं सोचते कि किससे युति होनी चाहिए और किससे नहीं। हम केवल महाराष्ट्र के हित में राजनीति करते हैं। आज राज्य को १६ लाख करोड़ रुपये के निवेश करार के साथ पहले स्थान पर लाया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास जारी हैं और गांव-गांव में पानी पहुंचाना, सूखे को अतीत बनाना, यही हमारी दिशा है। हमने २०१४ के बाद जो कहा, वह करके दिखाया। हम केवल भाषण देने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए रविंद्र चव्हाण की नियुक्ति के अवसर पर फडणवीस ने उन्हें धाडसी और २४/७ पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में पद खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि विचारधारा और कार्य के आधार पर मिलते हैं।

चंद्रशेखर बावनकुळे की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा को खड़ा करने में अथक मेहनत की। फेक नैरेटिव को हमने सच्चाई से जवाब दिया और १३५ सीटें जीत कर भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई।

अंत में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि मोदीजी ने भारत में ही नहीं, विश्व में एक प्रभावशाली नेतृत्व खड़ा किया है और ११ वर्षों में २५ करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य किया है।

शेतकऱ्यांचा अपमान: मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग पर विपक्ष का विधानसभा कार्यवाही से बहिष्कार

रिपोर्ट: जमीर काज़ी । मुंबई, २ जुलाई

महाराष्ट्र विधानसभा के पावसाळी अधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रमक रुख अपनाया। विपक्ष ने किसानों का बार-बार अपमान किए जाने पर मुख्यमंत्री से माफी की मांग की और कार्यवाही का बहिष्कार किया।

कार्यवाही की शुरुआत में भाजपा के पूर्व मंत्री बाबनराव लोणीकर द्वारा किसानों के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने तीव्र विरोध जताया। महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने कहा कि शेतकऱ्यांविरोधात वारंवार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और मुख्यमंत्री एक स्पष्ट माफी दें।

घोषणाबाज़ी के दौरान कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने अध्यक्ष की सीट के पास जाकर राजदंड (गदा) उठाने की कोशिश की, जिससे सदन में हंगामा मच गया। इसके कारण सदन की कार्यवाही पाँच मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

बाद में अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नाना पटोले को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया। इस निर्णय के विरोध में महाविकास आघाड़ी के सभी विधायकों ने पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सभात्याग किया।

विधानसभा में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जब किसान सड़कों पर आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं, सरकार के मंत्री और विधायक किसानों के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जो आवाज़ उठाता है, उसे निलंबित किया जाता है।

वडेट्टीवार ने कहा, अगर किसानों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़ा तो हम तैयार हैं, लेकिन किसानों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बता दें कि राज्य में इस समय शक्तिपीठ महामार्ग के विरोध में १२ जिलों में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा विधायक बाबनराव लोणीकर द्वारा यह कहना कि किसान हमारे पैसों पर जीवित हैं, को विपक्ष ने अपमानजनक बताते हुए सरकार पर किसानों का समर्थन न करने का आरोप लगाया।

महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया कि वे किसानों के पक्ष में संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे सरकार कोई भी कार्रवाई क्यों न करे।

जमीयत उलमा एक वैचारिक और सैद्धांतिक संगठन है - हमें इस संगठन से औपचारिक नहीं, बल्कि वैचारिक और वास्तविक रिश्ता रखना चाहिए: मौलाना महमूद असअद मदनी

प्रेस विज्ञप्ति । हैदराबाद, जुलाई २०२५

जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी साहब ने कहा कि जमीयत उलमा एक वैचारिक और सैद्धांतिक संगठन है, इस लिए हमारा संबंध इससे औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक और फिक्री (वैचारिक) होना चाहिए। वे जमीयत उलमा तेलंगाना की छह माह की एक दिवसीय सलाहकारी बैठक में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे, जो कि होटल पार्क कॉन्टिनेंटल, मेहदीपटनम, हैदराबाद में हज़रत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम की शुरुआत क़ारी मोहम्मद यूनुस अली ख़ान की तिलावत और मौलाना इनायतुल्लाह की नात से हुई। इसके बाद राज्य सचिव हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने राज्य जमीयत की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले ३० वर्षों से मौलाना शब्बीर अहमद साहब की सरपरस्ती में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जिलों, तालुकों और मंडलों में जमीयत की इकाइयों को मज़बूती मिली है।

मौलाना महमूद असअद मदनी ने ज़ोर देते हुए कहा कि आज जमीयत से जुड़ना देश और मिल्लत दोनों के लिए लाभकारी है। यह संगठन सरकार के स्तर पर भी मुस्लिम समाज की एक मज़बूत आवाज़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि आज हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इस कमी को अपने ईमान की कमी का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जमीयत के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह तआला उसे वैसी जगह से कामयाबी देता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।

उन्होंने यह भी कहा कि मिल्लत को संगठित करने के लिए जमाअत की ज़रूरत है, और जमीयत के सभी कार्यक्रमों को ज़िला व मंडल स्तर तक पहुंचाया जाए। ख़ास तौर से मौजूदा हालात में, नई पीढ़ी की फिक्री सुरक्षा, दीन और ईमान की हिफाज़त तथा सुधार समाज की तामीर के लिए हर शहर, गांव और मोहल्ले में मकातिब दीनिया और जमीयत के विभिन्न विभाग स्थापित किए जाने चाहिए।

मौलाना हकीमुद्दीन क़ासमी, महासचिव जमीयत उलमा-ए-हिंद, ने अपने भाषण में कहा कि जमीयत से जुड़ाव दीनी होना चाहिए और इसके तमाम कार्यों को दीन समझकर ही अंजाम देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में जमीयत द्वारा चलाई जा रही मकातिब की व्यवस्था के ज़रिये हम अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत कर सकते हैं।

कार्यक्रम में जमीयत तेलंगाना के नायब सदर मौलाना अब्दुल क़वी ने रुकनियत (सदस्यता) और जमीयत की अहमियत पर प्रकाश डाला। विभिन्न विभागों पर भी जिम्मेदारों ने रिपोर्ट पेश की:

मौलाना उमर मुहय्युद्दीन (शैक्षणिक बोर्ड) मौलाना अब्दुर्रहमान अतहर (स्टडी सेंटर)

मौलाना अब्दुल्ला अज़हर क़ासमी (जैम डिपार्टमेंट) मुफ्ती यूसुफ़ नोमानी (तहफ्फुज़े मदरसे) मुफ्ती यासिर नदीम (इस्लाहे मुआशरा) मुफ्ती सादिक हुसैन (मिल्लत फंड)

मुफ्ती अब्दुल मुइज़ शम्सी (तहफ्फुज़े औक़ाफ़) क़ारी यूनुस अली ख़ान (नई सदस्यता) मुफ्ती अब्दुस्सबूर (यूथ क्लब)

मौलाना मुफ्ती अब्दुल मलिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तथा मौलाना अब्दुस्सत्तार, खज़ांची जमीयत तेलंगाना ने भी संबोधित किया। मुफ्ती इलियास अहमद (जिला नर्मल) ने जमीयत की अहमियत पर तफ्सील से चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि १५ से २० जुलाई तक जमीयत तेलंगाना की ओर से सदस्यता अभियान, मदरसों-मस्जिदों और औक़ाफ़ की हिफाज़त के लिए राज्यभर में दौरे किए जाएंगे। इसके अलावा, जुलाई के आख़िरी दो जुमे सदस्यता अभियान के लिए निर्धारित किए गए हैं। उलेमा और खतीबों से अनुरोध किया गया है कि इन जुमों में जमीयत की अहमियत और सदस्यता को अपना विषय बनाएं। यह बैठक तीन सत्रों में संपन्न हुई। पहले सत्र की अध्यक्षता मौलाना पीर शब्बीर अहमद साहब, दूसरे की मौलाना अब्दुल क़वी साहब और तीसरे की मौलाना अब्दुस्सत्तार साहब ने की। अंतिम दुआ मौलाना ख्वाजा कलीमुद्दीन असअदी की सरपरस्ती में हुई।

बैठक में जमीयत उलमा तेलंगाना के ३३ जिलों के जिम्मेदारों और गणमान्य उलेमा ने भाग लिया। अंत में हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर ने मौलाना मदनी, मौलाना हकीमुद्दीन और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com